केबल टेलीविजन नेटवर्क में डीएएस कार्यान्वयन के लिए 16 अगस्त, 2012 को आयोजित की गई कार्य बल की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

केबल टेलीविजन नेटवर्क में डीएएस के कार्यान्वयन पर कार्यबल की 15वीं बैठक अपर सचिव की अध्यक्षता में 16.8.2012 को आयोजित की गई थी।

2. सदस्यों के स्वागत के पश्चात अपर सचिव ने सलाहकार को कार्य बल की पिछली बैठक के पश्चात प्रगति पर प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा। सलाहकार द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

i. 3 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 49,208 एसटीबी और 10 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 35,449 सेट टाप बाक्स लगाए गए हैं।

ii. चार महानगरों में 133 लाख एसटीबी (राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ द्वारा 114 लाख और स्वतंत्र एमएसओ द्वारा 19 लाख) की कुल अनुमानित आवश्यकता के विरूद्ध 10 अगस्त तक 42.50 लाख एसटीबी लगाए गए है जो लगभग 32 प्रतिशत उपलब्धि है। चार महानगरों में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति सप्ताह लगभग 11 लाख एसटीबी लगाना अब अपेक्षित है।

iii. दिल्ली में स्वतंत्र एमएसओ के साथ 13 अगस्त को बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 10 में से 9 पंजीकृत एमएसओ ने भाग लिया। बैठक के दौरान उभरे निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों की मुख्य-मुख्य बातें निम्न हैं :

- अभी तक कोई करार हस्ताक्षरित नहीं किया है - एग्रीगेटरों का कड़ा रूख
- एलसीओ एसटीबी नहीं लगा रहे
- प्रचार अभियान अवश्य शुरू किया जाना चाहिए
- टीआरएआई को बातचीत के लिए स्वतंत्र एमएसओ भी अवश्य बुलाना चाहिए

यह भी बताया गया कि एमएसओ को बिना विफलता के साप्ताहिक लगाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और स्वामी केबल को प्रदान की गई अस्थायी अनुमति की समीक्षा किए जाने की जरूरत है क्योंकि उसने न तो कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया है और न ही डाटा प्रस्तुत किया है।

iv. टीआरआई ने प्रसारकों और एमएसओ के बीच करारों को पूरा करन के लिए 21 अगस्त तक का समय विस्तार दिया है। यद्यपि अभी किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, फिर भी राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ को आशा है कि 21 अगस्त से पहले कम से कम प्रमुख एग्रीगेटरों के साथ करारों पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्वतंत्र एमएसओ के साथ करार केवल राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ के साथ समझौता होने के पश्चात संभव होगा।

v. उप-समूह की दूसरी बैठक 8 अगस्त को आयोजित की गई थी। एनबीए और आईबीएफ के प्रनिनिधि बैठक में भाग नहीं ले सके। उप-समूह के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे :

- सभी टीवी चैनलों पर एक ही समय पर विज्ञापन के साथ ब्लैक आउट तत्काल शुरू हो जाने चाहिए क्योंकि एसटीबी लगाने में तेजी नहीं आ रही है।
- मुद्रण सहित सरकार से विज्ञापन दिए जाने चाहिए क्योंकि जनता डिजिटाइजेशन में जाने की तारीख के बारे में आशांकित है।

यह बताया गया था कि निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :

- एनबीए और आईबीएफ को ब्लैक आउट का विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा गया है।
- डीएवीपी ने 3 टीवी स्पाट प्रस्तुत किए है इन स्पाट में मामूली परिवर्तन किए जा रहे हैं और अंतिम स्पाट 21 अगस्त तक प्रसारण के लिए तैयार हो जाएंगे।
- आकाशवाणी ने रेडियो जिंगल को (6 से) बढ़ाकर कम से कम आठ बार दिन में कर दिया है।

- रेडियो जिंगल को निजी एफएम चैनलों पर प्रसारित करने के लिए एआरओआई को भेजा गया है। चैनलों के ब्यौरे और विज्ञापन की बारम्बारता एकत्रित की जा रही है।
- मुद्रित विज्ञापन का मसौदा तैयार किया गया है। इस पर अंतिम रूप देने के लिए फिक्की के प्रतिनिधि के साथ चर्चा की गई थी।

vi. 52 आवेदनों में से 46 को पंजीकरण के पत्र जारी किए गए हैं। 4 आवेदन अभी प्रस्तुत करने है और 2 संवीक्षाधीन है क्योंकि आवेदनों में कमियों के लिए उनसे उत्तर प्राप्त हो गया है।

vii. मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई की जा रही है :

क. सभी टीवी चैनलों पर विडियो विज्ञापन शुरू करना।

ख. साफ्टवेयर में डाटा संग्रहण पहले ही शुरू किया जा चुका है।

ग. ब्लैक आउट विज्ञापन पर अनुवर्ती कार्रवाई

घ. एसपीवी प्रस्ताव पर आईएफडी के साथ चर्चा की गई-आईएफडी द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने की जरूरत है।

ङ. 38 फेस-II शहरों अर्थात निगमायुक्तों/क्लेक्टरों की सितम्बर में विज्ञान भवन में बैठक

3. इसके पश्चात, एमएसओ सहयोग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि एक राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ ने पहले ही एक प्रमुख प्रसारक के साथ करार पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ ने भी एक खेल प्रसारण के साथ वाणिज्यिक समझौता निष्पन्न किया है परन्तु अभी करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

4. आईबीएफ के प्रतिनिधि ने बताया कि एक प्रसारक ने चार एमएसओ के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं (न कि एक जैसा कि एमएसओ सहयोग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है)। उन्होंने बताया कि बहुत से करार आज हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

5. सीओएफआई के प्रतिनिधि ने कहा कि यह सही नहीं है कि एलसीओ एसटीबी नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि एमएसओ एलसीओ को एसटीबी नहीं दे रहे हैं। अपर सचिव के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि हेथवे, इन केबल और डिजिकेबल के एमएसओ एसटीबी नहीं दे रहे हैं। अपर सचिव ने बताया कि एसटीबी की आपूर्ति न करना किसी एमएसओ के हित में नहीं है क्योंकि वे सभी, डिजिकेबल को छोड़कर, के पास एसटीबी स्टाक में हैं। इसलिए ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

6. उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधि ने बताया कि उसके पास उपभोक्ताओं से फीडबैक है जिसमें उन उपभोक्ताओं जिन्होंने एसटीबी लिए है स्वयं की तुलना उनसे कर रहे हैं जिन्होंने अभी एसटीबी नहीं लिए हैं और नाखुश है कि उन्हें अनावश्यक अदा करना पड़ा। तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि अंतत: प्रत्येक को एसटीबी खरीदना हो इसलिए वे जिन्होंने एसटीबी प्राप्त कर लिया है बेहतर हैं क्योंकि वे पहले ही डिजिटल सिगनल प्राप्त कर रहे हैं।

7. अपर सचिव के एक प्रश्न पर बीईसीआईएल के प्रतिनिधि ने बताया कि अरासू केबल ने अभी तक चेन्नई के लिए वाणिज्यिक बोली नहीं खोली है।

8. सीईएएमए के प्रतिनिधि बताया कि लगभग 3 लाख एसटीबी पहले ही सप्लाई किए जा चुके हैं और शेष 3 लाख एसटीबी की आपूर्ति अक्टूबर, 2012 तक पूरी हो जाएगी। एक प्रश्न पर बताया कि लगभग 6000 एसटीबी का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है।

9. सीआईआई के प्रतिनिधि ने बताया कि सचिव प्रसारण की सलाह पर दिल्ली में 30 अगस्त, 2012 को डीएएस के परस्पर संपर्क कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि टीआरएआई के अध्यक्ष ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। अपर सचिव ने सुझाया कि सभी हितधारकों, विशेष रूप से कुछ प्रसारकों जो न तो आईबीएफ और न ही एनबीए, एफटी चैनलों और लोग जिनके सुदृढ़ स्थानीय चैनल है, को शामिल किया जाए।

10. सम्पन्न करते समय अपर सचिव ने निम्नलिखित सुझाव दिए :

i. प्रसारक/एमएसओ करारों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं परन्तु यदि वे दरें प्रकट नहीं करना चाहते तो इन करारों की प्रतियों को टीआरएआई को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं कि सभी करारों के हस्ताक्षर होने तक प्रकट न करे। जब 21 अगस्त के पश्चात टीआरएआई दरों की एकतरफा घोषणा करेगा तो यह जिन्होंने पहले ही हस्ताक्षर कर लिए है के लिए अलाभकारी नहीं होगा।

ii. राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ को उन एलसीओ की सूची सप्लाई करने के लिए कहा था जो एसटीबी नहीं लगा रहे हैं। दिल्ली के लिए केवल एक एमएसओ को सूची प्राप्त हुई है। सभी एमएसओ को यह सूची तत्काल सप्लाई करनी चाहिए।

iii. एलसीओ को डिजिटाइजेशन प्रोसेस में सहयोग के लिए सलाह दी जानी चाहिए।

iv. यह सभी हितधारकों के हित में है कि अभिदाताओं का सही डाटा दर्शाएं ताकि केबल अभिदाताओं में वृद्धि के साथ राज्य सरकारें भी करों में कटौती पर विचार करें।

v. सभी 26 चैनल एग्रीगेटरों की बैठक मंत्रालय में बुलायी जाए।

11. बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ समाप्त हो गई।